कच्चे रेशम के आयात के लिए चीन के साथ द्विपक्षीय समझौता

9. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने 250 टन कच्चे रेशम के आयात के लिये हाल ही में चीन के साथ एक द्विपक्षीय समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि चीन से कच्चे रेशम के आयात से देश के रेशम उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या भविष्य में चीन से कच्चे रेशम का आयात नहीं किया जायेगा; और

(ङ) इस सम्बन्ध में नीति का व्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां ।

(ख) कर्नाटक के विभिन्न भागों में सूखा पड़ने, दक्षिणी रेशम उद्योग राज्यों में यूजी फलाई संकट, कच्चे रेशम आदि की मांग में वृद्धि होने की वजह से 1981 के दौरान कच्चे रेशम की कीमत में काफी वृद्धि हो गई थी । इसलिये सरकार ने कच्ची रेशम की ऊंची कीमतों की वजह से उत्पन्न स्थिति पर काबू पाने के लिये विभिन्न राज्यों में हथकरघा बुनकरों को सहायता पहुंचाने के लिये चीन से 250 मी० टन कच्चा रेशम आयात करने का विनिश्चय किया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) अगर घरेलू बाजार स्थिति के कारण यह आवश्यक होगा तो कच्चे रेशम का आयात करने की अनुमति दी जाएगी ।

(ङ) वर्तमान आयात नीति के अनुसार, कच्चे रेशम का आयात गुणावगुण के आधार पर करने की अनुमति है और यह केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अभिकरण के माध्यम से मार्गीकृत है;

Financing of sick Industrial units

10. SHRI NAVIN RAVANI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether any instructions have been issued to the commercial banks and other financial institutions to make concerted and timely efforts in financing sick Industrial units and making them viable; and

(b) if so, what are the details thereof and how many sick industrial units have been benefited under the scheme in the country and particularly in Gujarat State during the year 1981?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY): (a) and (b). With a view to effectively tackle the sickness prevailing in industries, Government have formulated various policy measures and the banks and the financial institutions have been advised to implement the same. The Government constantly reviews the situation and modifications to the existing schemes and policies are carried out where necessary. The process is continuous and the banks and institutions take effective steps for implementing the Government's decisions.

As per the present policy of the Government, the banks and financial institutions must take all possible steps to detect and prevent sickness in the incipient stage itself and rehabilitate the viable sick units to the extent possible. In accordance with this policy, banks draw up rehabilitation programmes in respect of the potentially viable units on a case by case basis. The assistance packages are tailor-made to suit the particular re-